नगर निगम को लूट रहा 'गूजर का बेटा'

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का ढिंढोरा पीटने वाले सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में नगर निगम भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वर्तमान में निगम के एक्सईएन ओमदत्त की चर्चा जोरों पर है, निगम कर्मियों का मानना है कि भ्रष्टाचार में ओमदत्त तो पूर्व चीफ इंजीनियर डीआर भास्कर से कहीं आगे है, मोटे कमीशन की एवज में कोई भी अवैध, नियम विरुद्ध काम करने को सदैव उपलब्ध केंद्रीय मंत्री किशन पाल गूजर का वरद्हस्त होने के कारण ओमदत्त निगमायुक्त तक को ठेंगे पर रखता है। एक्सईएन होने के नाते निगम के अधिकतर विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पर उसने कब्जा कर रखा है।

नगर निगम में दो सौ करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुए साढ़े तीन साल बीत चुके हैं। सत्ता पक्ष के मंत्रियों-नेताओं और आईएएस अफसरों की मिलीभगत से हुए इस घोटाले में तत्कालीन चीफ इंजीनियर डीआर भास्कर, लेखा विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदार सतबीर की गिरफ्तारी कर सरकार ने वाहवाही लूटी और अपने मंत्री व भ्रष्ट आईएएस अफसरों को बचाने के लिए जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई।

आईएएस अफसरों की कठपुतली कहे जाने वाले खट्टर ने इस घोटाले का खुलासा होने के बाद आईएएस अफसरों की जवाबदेही खत्म करने के उद्देश्य से एक करोड़ रुपये तक के काम कराने का अधिकार नगर निगम के एक्सईएन को दे दिया। यदि खट्टर सच में ईमानदार होते तो एक्सईएन की यह शक्ति नहीं बढ़ाते लेकिन उन्होंने अपने मंत्रियों की लूट कमाई बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था कर डाली।

भ्रष्टाचार का पर्यायवाची : ओमदत्त एक्सईएन

केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर का खास होने के चलते फर्जी डिग्री के बावजूद ओमदत्त नगर निगम में एसडीओ से एक्सईएन पद तक आसानी से पहुंच गया, इस दौरान उसकी फर्जी डिग्री की जांच चल रही है और सेवानिवृत्त होने तक चलती रहेगी। एक्सईएन की कुर्सी पर बैठने के बाद ओमदत्त अपने आका गूजर के इशारे पर काम कर रहा है। भ्रष्टाचार और मोटी कमाई की लालच में एक करोड़ रुपये से कहीं अधिक कीमत वाले विकास कार्यों को दो से तीन हिस्सों में तोड़ कर कराया जाता है ताकि एक्सईएन ही सारे टेंडर जारी कर सके। उसके डिवीजन में शायद ही कोई विकास कार्य एक करोड़ से अधिक का हुआ हो। निगम के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार ई टेंडर प्रक्रिया सिर्फ देखने के लिए है, सारा काम उसकी मर्जी से ही होता है। टेंडर मिलता उसी ठेकेदार को है जिसकी सिफारिश आका गूजर ने की हो। ठेकेदार को टेंडर लेने के लिए सात से आठ प्रतिशत कमीशन पहले ही देना होता है। जिस ठेकेदार को टेंडर देना होता है, ई-टेंडरिंग में सिर्फ उसकी और दो तीन डमी कंपनियों की बिड लगती है, अन्य असली ठेकेदारों की बिड सिस्टम कोई न कोई कमी बता कर रिजेक्ट कर देता है। कुछ खास ठेकेदारों के गुट को ही ओमदत्त काम देता है। बताया जाता है कि ये ठेकेदार उसके लिए जूते मोजों से लेकर महंगे सूट, मोबाइल आदि का इंतजाम करते हैं।

बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर ओमदत्त को अपने बेटे की तरह मानते हैं, यही कारण है कि उस पर कोई आंच नहीं आने देते। संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि चंडीगढ़ मुख्यालय से ओमदत्त का ट्रांसफर दूसरे जिले में कर दिया गया लेकिन मंत्री के आदेश पर उसे रिलीव नहीं किया गया और चंद दिनों में ही तबादला आदेश रद्द कर दिया गया। नगर निगम में सहायक अभियंता पद पर रहते हुए रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस की गिरफ्त में आया था लेकिन मंत्री गूजर के कारण उसका कुछ नहीं हुआ।

निगम कर्मचारियों में यह भी चर्चा है कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की अथाह कमाई से ओमदत्त ने मच्छगर, होडल में काफी बेनामी संपत्ति बना डाली है। कुछ समय पहले मच्छगर में अपनी इसी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए बाउंड्री करवाने पहुंचा था तो गांव वालों ने उसे जमकर पीटा था, तब भी किशनपाल ने दोनों पक्षों में समझौता कराया था। किशनपाल से करीबी का अंदाजा इसी बात से भी समझा जा सकता है कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र तो इसको दिया ही गया है अतिरिक्त लूट कमाई के लिए निगम में जोड़े गए 27 गांवों के 'विकास' का भी जिम्मा इसे दिया गया है। इन गांवों में राजपाल मामा और केंद्रीय मंत्री के इशारे पर उनके सजातीय गुर्गों को विकास कार्य की रेवड़ी बांटने के लिए ही उसे लगाया गया है। जानकार सूत्रों के अनुसार जब कोई उससे पूछता है कि भ्रष्टाचार में पकड़े जाने का भय नहीं है क्या तो कहता है कि जांच अधिकारियों के मुंह में इतना पैसा भर दूंगा कि उनकी आंखें बंद हो जाएंगी।

ओमदत्त के भ्रष्टाचार के कारण निगम की बदनामी से दुखी कुछ अधिकारी कहते हैं कि यदि जांच हो जाए तो डीआर भास्कर का दो सौ करोड़ रुपये का घोटाला बहुत छोटा साबित होगा। एक्सईएन ने खुली लूट मचा रखी है जैसे उसे कायदे-कानून और नियमों का कोई खौफ ही नहीं है।

ईमानदारी का झूठा नारा लगाने वाले खट्टर को नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्टाचार की जानकारी न हो ऐसा नहीं हो सकता। उनकी ही पार्टी के पार्षद व अन्य जन प्रतिनिधि नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। वह खुद सार्वजनिक मंच पर नगर निगम में भ्रष्टाचार की बात कुबूल चुके हैं फिर भी निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के कोई कदम नहीं उठाते, उठाएं भी कैसे निगम की इस काली कमाई में उनकी ही पार्टी के लोग लगे हुए हैं।

सवाल तो निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास पर भी बनता है, अगर मंत्री गूजर और ओमदत्त ने ही शहर को लूट कर खाना है तो वे यहां क्यों बैठी हैं? या तो वे इस लायक नहीं कि उक्त लूट पाट को देखकर उस पर अंकुश लगा सकें या फिर वे खुद भी इस लूट में शामिल हो सकती हैं, फैसला खुद कर लें।

भाजपा के बड़बोले दावों का समय है लेकिन क्या कांग्रेस मुक्त भारत संभव है? नहीं।

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

दिसंबर 2023 के राज्य विधानसभा नतीजों का राजनीतिक संदेश यही है। पार्टी की दक्षिण में तेलंगाना की जीत में ही नहीं, उत्तर में तीन राज्यों की हार में भी। कांग्रेस मुक्त भारत कदापि संभव नहीं।

कांग्रेस पार्टी जिस अखिल भारतीय अपील वाली राजनीति के प्रतिनिधित्व का दावा कर सकती है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा को गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह की विरासत को मटियामेट करना होगा जो फिलहाल संभव नहीं। न ही स्वतंत्र भारत में नेहरू, इंदिरा के ऐतिहासिक योगदान को एकाएक नकार पाना।

हां, ठीक है, इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करीबी मुकाबला करते हुए भी वे एंटी इनकंबेंसी और आंतरिक कलह का शिकार हुए, लेकिन, मानना होगा कि यह कांग्रेस शासन का चरित्र चला आ रहा है। इसमें नया कुछ नहीं, वही वोटर इस पार्टी को सत्ता में फिर वापस लायेगा।

मध्य प्रदेश में जीत के लिए कमलनाथ मुक्त कांग्रेस होनी चाहिए थी। भारत जोड़ो यात्रा के मूल्यों और ऊर्जा को आगे ले जाती युवा नेतृत्व वाली कांग्रेस, जैसे कि तेलंगाना में दिखा। जबकि कमलनाथ के प्रचार अभियान का स्वरूप भाजपा की बी टीम की राह पर ही छद्म सांप्रदायिक था, और उनकी 2018/19 की महीनों चली भ्रष्ट और दिशाहीन सरकार का ट्रेलर शिवराज चौहान की 18 वर्षों की एंटी इनकंबेंसी पिक्चर के समक्ष भी बेहद फीका सिद्ध हुआ।

2024 में कांग्रेस जरूरी नहीं कि उत्तरी राज्यों में भाजपा से ऐसे ही पिटे, बेशक वे संगठन के मामले में भाजपा से मीलों पीछे हैं और रहेंगे। लेकिन आज भी उनके पास तीन राज्यों में अपनी सरकारें हैं। जैसा केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाया है कि वोटर एक अपेक्षाकृत बेहतर प्रशासन से मिलने वाले फलों के लिए भी उत्सुक रहता है। भाजपा की तमाम सरकारें, प्रशासनिक रूप से लगातार फिसड्डी साबित होती आ रही हैं। केंद्र में स्वयं पीएम मोदी की प्रशासनिक अक्षमताएं, व्यापक प्रचार तंत्र के बावजूद, छिपाए नहीं छिपती।

क्या कांग्रेस के कर्ता धर्ता, हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना में अपनी घोषणाओं के अनुरूप फल दे सकने में सक्षम एक जनवादी प्रशासनिक मॉडल साकार करने की सोच सकते हैं? 2024 चुनाव ज्यादा दूर नहीं।

पुलिस-प्रशासन की शह पर ट्रांसपोर्टर ने कब्जाई सरकारी ज़मीन, जन दबाव के आगे झुकी पुलिस

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सोहना रोड पर स्थित गौंछी शमशान घाट के निकट तथा पुलिस चौकी संजय कॉलोनी के सामने करीब डेढ़ एकड़ खाली पड़ी सरकारी ज़मीन पर मां वैष्णो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कब्जा कर रखा है। बताया जाता है कि इस कम्पनी के पास छोटे-बड़े 100 के करीब ट्रक व ट्राले हैं। इनमें से 25-30 वाहन सदैव ही इस भूखंड पर खड़े रहते हैं। इसकी वजह से सोहना रोड पर अक्सर जाम लगता रहता है। किसी शव यात्रा के आने पर तो जाम की स्थिति बद से भी बदतर हो जाती है क्योंकि शव यात्रा में सैंकड़ों लोग व अनेकों छोटे-बड़े वाहन आते हैं, जिन्हें सड़क पर ही खड़ा होना पड़ता है।

ट्रांसपोर्टर के इस अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोग अनेकों बार थाना मुजेसर सहित सभी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायतें दे चुके हैं। इसके बावजूद कब्जा ज्यों का त्यों चला आ रहा है। हां, एक बार हनीफ कुरैशी ने बतौर पुलिस आयुक्त इस कब्जे को जरूर हटवाया था लेकिन उनके बाद फिर से कब्जा बहाल हो गया। कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मामले की शिकायत सीएम विंडो पर भी लगाई थी। लेकिन वह भी ठंडे बस्ते में चली गई। शायद उन लोगों को यह नही पता था कि सीएम विंडों भी एक बड़ा फ्रॉड है।

इस सबके बावजूद स्थानीय लोगों ने हार नहीं मानी, वे लगातार उसके विरुद्ध आवाज उठाते रहे। जानकारों के मुताबिक जब यह मसला डीसीपी ट्रैफ़िक अमित यशवर्धन के नोटिस में आया तो उन्होंने सम्बन्धित ट्रैफिक पुलिस अधिकारी (जेडओ) को अच्छा-खासा हड़काया। बस फ़िर क्या था मसला हल हो गया, सरकारी जगह खाली हो गई और जाम लगना बंद हो गया।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।